राजस्थान में भाजपा नेतृत्व ने तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए

केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया है

- **रविवार को पर्यवेक्षकों द्वारा विधायक दल की बैठक लेने की संभावना है। पर्यवेक्षक विधायकों से बात कर उनकी मंशा जानेंगे।**
- **इस बार भाजपा में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। इसलिए नेतृत्व सावधानी से फैसला करना चाहता है।**
- **ऐसी भी चर्चा है कि, हरियाणा की तरह संघ से जुड़े किसी व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसलिए सुनील बंसल व निंबाराम का नाम भी लिया जा रहा है।**

जयपुर, 8 दिसम्बर (का.सं.)। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन के लिए भाजपा ने एक कदम आगे बढ़ा लिया हैं। भाजपा ने राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ ही राजनैतिक हलचल तेज हो गई है। रविवार को पर्यवेक्षकों के द्वारा विधायक दल की बैठक लेने की संभावना हैं।

भाजपा के ये तीनों दिग्गज अब प्रदेश के सभी विधायकों से बातचीत करेंगे और फिर पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इन ऑब्ज़र्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर ही राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनेगा। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चुने जाने के बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम का ऐलान किया जाएगा और वहां औपचारिक सहमति ली जाएगी।

इसके बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख तय की जाएगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसम्बर को आ चुके हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत होने के बाद भी भाजपा मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद राज्य में किसी भी तरह की गुटबाजी के चलते पार्टी में विभाजन न हो जाए। इसलिए मुख्यमंत्री के चयन पर भारी दुविधा है।

राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार तो कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। उन्होंने विधायकों को अपने घर बुलाकर और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर शक्ति प्रदर्शन भी शुरु कर दिया है। चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जमीनी स्तर पर किए गए काम की वजह से भाजपा को भारी बहुमत मिला है। ऐसे में पार्टी के भीतर की गुटबाजी को दबाने के लिए हरियाणा वाले फॉर्मूले पर भी काम किया जा सकता है और आर.एस.एस. से संबंधित किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस संभावना ने सुनील बंसल और निंबाराम को भी मुख्यमंत्री पद की रेस में ला दिया है। अब भाजपा के पर्यवेक्षक विधायकों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार का चयन करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे।

राज्यसभा में 70 से अधिक निजी विधेयक पेश किये गये

नयी दिल्ली 8 दिसम्बर। राज्यसभा में शुक्रवार को 70 से अधिक निजी विधेयक पेश किये गये। उच्च सदन में शुक्रवार का दिन सदस्यों के निजी विधेयकों के लिए निर्धारित रहता है।

आज सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों ने 70 से अधिक अलग अलग विधेयक पेश किये जिनमें वक्फ बोर्डों को निरस्त करने से संबंधित निजी विधेयक 'वक्फ निरस्त विधेयक 2022' भी शामिल है।

- **इसमें वक्फ बोर्डों को निरस्त करने का विधेयक भी शामिल है।**

भारतीय जनता पार्टी के हरनाथ सिंह यादव ने यह विधेयक पेश किया। सदन में कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया लेकिन इस प्रस्ताव को 32 के मुकाबले 53 मतों से अस्वीकार कर दिया गया।

सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी निजी विधेयक पेश किये जाने के बाद कहा कि आज विधेयक पेश करने में काफी समय लगा है इसलिए कार्यवाही का समय सवा पांच बजे तक बढ ाया जा रहा है।

राजनाथ सिंह को राजस्थान में पर्यवेक्षक क्यों बनाया गया है?

- **राजनाथ सिंह बेहद अनुभवी एवं वरिष्ठ नेता हैं तथा पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं इसलिए उनका सभी सम्मान करते हैं।**
- **राजनाथ सिंह जब पहली बार भाजपा अध्यक्ष बने थे तब वसुंधरा राजे राज्य में मुख्यमंत्री थीं, इसलिए राजनाथ सिंह का वसुंधरा से तालमेल रहा है।**
- **इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के जितने भी दावेदार हैं राजनाथ सभी से सीनियर हैं और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते सभी राजनाथ सिंह के मातहत रहे हैं। इसलिए राजनाथ सिंह सभी को समझा सकते हैं।**

जयपुर, 8 दिसम्बर (का.सं.)। भाजपा ने प्रदेश का चुनाव तो बहुमत के साथ जीत लिया है, लेकिन पार्टी में अब मुख्यमंत्री पद का खिताब किस नेता को दिया जाए इस पर रार हो रही है। ऐसे में भाजपा ने पर्यवेक्षकों के जरिए इस जटिल मसले को सुलझाने का प्रयास किया है। पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश के महत्व को समझती है इसलिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर उलझे मसले को सुलझाने के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर और अनुभवी नेता को ही पर्यवेक्षक बनाया है।

दरअसल राजनाथ सिंह भाजपा के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, जो जमीनी स्तर से उठकर, संगठन में होते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पद तक पहुंचे। वो दो बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली बार 2005 से 2009 तक वो इस पद पर रहे। वहीं साल 2013 में जब नितिन गडकरी ने भाजपा प्रमुख पद से इस्तीफा दिया तब भी पार्टी के बड़े ही कमजोर मोड़ पर सिंह ने ही अध्यक्ष पद की कमान संभाली और 2014 तक इस पद पर रहे। उन्ही के कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी चुनाव जीते और प्रधानमंत्री भी बने। भाजपा को हर संकट की घड़ी में जिस मजबूत चेहरे की जरूरत होती है, उनमें से एक राजनाथ सिंह भी हैं। अब राजस्थान में भाजपा के सामने मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय है और साथ ही पार्टी में अंदरूनी कलह का संकट भी है, तो राजनाथ सिंह ही एक ऐसे संकटमोचक के रूप बनाया है।

दरअसल राजनाथ जब भाजपा के पहली बार अध्यक्ष थे, तब राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थीं। ऐसे में उनका वसुंधरा से पुराना तालमेल रहा है और वसुंधरा ही मुख्यमंत्री पद को लेकर मुख्य चुनौती भी खड़ी कर रही हैं। वसुंधरा मजबूत क्षेत्रीय नेता है और 2014 से पहले से पहले वाली भाजपा की बड़ी नेता रही है।

राजनाथ सिंह ने भाजपा अध्यक्ष पद लाल कृष्ण आडवाणी से लिया था और अमित शाह को सौंपा था यानी वो भाजपा के परिवर्तन युग की कड़ी रहे हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह ही वो नेता हो सकते हैं जो वसुंधरा राजे का सामना कर सकते हैं। राजनाथ सिंह पार्टी से शुरु से जुड़े रहे है और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ में भी लंबे समय तक काम कर चुके हैं। संघ, पार्टी संगठन और सरकार तीनों में ही उनका अच्छा अनुभव है। राजस्थान में उनका अनुभव काम आ सकता है। वसुंधरा के अलावा जिन सांसदों और मंत्रियों की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की जा रही है, राजनाथ उन सभी से सीनियर हैं। उन सभी को समझाने और समझने में राजनाथ सिंह बेहतरीन विकल्प हैं।

शादी समारोह में 6 साल की बालिका से दुष्कर्म

- **चिकित्सकों ने बताया कि बालिका की हालत स्थिर है।**
- **एडीशनल एस.पी. के नेतृत्व में टीम गठित की गई है तथा आरोपी की तलाश की जा रही है।**

दौसा, 8 दिसम्बर (निसं)। जिला मुख्यालय स्थित एक होटल में शादी समारोह में उस समय सनसनी मच गई जब शादी में पहुंची 6 साल की बालिका के साथ अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया।

घरवालों के साथ शादी में शामिल होने गई 6 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद बालिका को गंभीर हालत में जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया है। मासूम के पिता ने दौसा के महिला थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। मामले की सूचना मिलने पर जयपुर रेंज आई.जी. उमेश दत्ता, जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जहां पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया एवं घटना से जुड़ी जानकारी ली।

जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता दौसा पहुंचे और कहा कि, पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच की जा रही है। मामले की जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारी भी टीम में शामिल हैं। जयपुर रेंज आईजी दत्ता ने कहा कि बच्ची के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है। अभी हालत स्थिर बनी हुई है। जयपुर से फॉरैन्सिक टीम दौसा पहुंच चुकी है। सभी पहलुओं को देखते हुए मामले की जांच की जा रही है, जांच अभी शुरुआती स्टेज पर है।

जयपुर रेंज आईजी दत्ता ने बताया कि, वे बच्ची के पिता और डॉक्टरों से मिले हैं तथा बच्ची की हालत के बारे में जानकारी ली। एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर एडिशनल एसपी को टीम का इंचार्ज बनाया गया है। मामले की जांच के लिए डॉग स्कॉड टीम को भी इसमें शामिल किया गया है। होटल के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। हर एंगल से जांच की जा रही है।

एसपी वंदिता राणा ने कहा कि, होटल के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपी की पहचान के प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना गुरुवार रात को उस वक्त की है, जब होटल के पास मैरिज गार्डन में शादी समारोह चल रहा था। घरवाले शादी में व्यस्त थे इसी दौरान मौका पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। काफी देर बाद जब घरवालों को ध्यान आया कि बच्ची गायब है तो उन्होंने उसको तलाश किया। मासूम गार्डन में नहीं मिली। होटल में गए तो बच्ची बदहवास हालत में मिली। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. शिवराम मीणा ने बताया कि, मध्य रात्री को पीड़ित बालिका को आपातकालीन यूनिट में लाया गया था। जहां चिकित्सकों द्वारा बालिका का प्राथमिक इलाज किया और बालिका की हालत गंभीर होने पर उसे अविलंब हायर सेंटर के लिए रैफर कर दिया।

'आई.सी.आई.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्णयों में "कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्ट्रैस्ट" (हितों का टकराव) उजागर किया। इससे कथित रूप से उनके पति दीपक कोचर को लाभ पहुंचा। जांच परिणामों के आधार पर, बैंक ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और उनके स्वैच्छिक त्यागपत्र को बर्खास्ती में बदल दिया। इससे अप्रेल 2009 से मार्च 2018 तक के उनके द्वारा एकत्रित व अर्जित सभी बोनस तथा स्टाक ऑप्शन निरस्त हो गये।

हरीश साल्वे, जो न्यायालय में कोचर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन पर लगाये गये एसेट फ्रीज (परिसम्पत्तियों को फ्रीज) को पलटवा नहीं सके। वे कोचर के दावे कि, 9,90,000 शेयर सी.ई.ओ. के रूप में उन्हें मिलने वाले वेतन-भत्ते आदि का भाग है, को स्वीकार नहीं करा पाये, यह निर्णय बैंक की आचरण संहिता तथा नैतिक मापदंडों को लागू करने के लिये हितों में टकराव नीतियों के उल्लंघन पर कठोर कार्यवाही करने के रूख को बल मिला।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कोचर के, देश में प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक आई.सी.आई.सी.आई. से अपनी परिसम्पत्तियों और लाभ वापस लेने की कानूनी लड़ाई को प्रभावी रूप से समाप्त कर देता है।

फोन टैपिंग केस में अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को होगी

सरकार बदलने के कारण राज्य सरकार के वकील ने एक-दो सप्ताह का समय मांगा है

- **राज्य सरकार के वकील संदीप झा ने कहा कि, केस में नई सरकार से निर्देश लेना होगा।**
- **कोर्ट ने गहलोत के ओ.एस.डी. रहे लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रखने का भी आदेश दिया।**

जयपुर, 8 दिसम्बर (का.प्र.)। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे एडवोकेट संदीप झा ने राजस्थान में सरकार बदलने की स्थिति में कहा कि केस में सरकार से निर्देश लेना होगा, लिहाजा 1-2 सप्ताह का समय दिया जाए। उधर शिकायतकर्ता की तरफ से उपस्थित वकील द्वारा कहा गया कि अब इस केस में कुछ बचा नहीं है, ये स्पष्ट है क्योंकि लोकेश शर्मा ने पिछले दिनों जो इंटरव्यू दिए हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनमें ये माना है कि उनकी जानकारी में ये फोन टैपिंग की गई है।

इस पर जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि इंटरव्यू और मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। इस पर शिकायतकर्ता के वकील द्वारा लगातार मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज आर्टिकल्स का हवाला देने पर लोकेश शर्मा के वकील ने कहा कि हमें नहीं पता कि शिकायतकर्ता के वकील जिन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, उनमें क्या लिखा गया है। इसलिए आप एफिडेविट फाइल कर दें, हम उस पर अपना जवाब दाखिल कर देंगे।

उधर राज्य सरकार की तरफ से मांगे गए समय और सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त करने के बाद ही आगे की बहस किए जाने की बात पर अब 19 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओ.एस.डी. रहे लोकेश शर्मा को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा और उन्हें कोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी।

गौरतलब है कि 11 अक्टूबर के बाद से विभिन्न कारणों के चलते मामले की सुनवाई लगातार टलती आ रही है। वहीं 11 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान लोकेश शर्मा के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने लोकेश शर्मा का पक्ष रखते हुए उन पर लगे फोन टैपिंग और दिल्ली पुलिस की ओर से जांच में सहयोग नहीं करने के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। 11 अक्टूबर को मामले में लोकेश शर्मा की तरफ से बहस अधूरी रह गई थी, जिसे अगली तारीख पर पूरी किया जाना था। अब मामले में अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को होनी है और तब तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रहेगी। बता दें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च 2021 में दिल्ली क्राइम ब्रांच में लोकेश शर्मा के खिलाफ फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं इस मामले में लोकेश शर्मा की ओर से केंद्रीय मंत्री की ओर से दर्ज करवाई गई एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की गई है।

कांग्रेस के पाले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नियंत्रित किया जो असदुद्दीन ओवैसी की ए.आई.एम.आई.एम. जैसी पार्टियां कर रही थीं। इसका असर ये हुआ कि ए.आई.एम.आई.एम. को अपने गढ़ माने जाने वाली हैदराबाद ओल्ड सिटी में ही संघर्ष करना पड़ा और उसके प्रत्याशियों की जीत का अंतर भी कम रहा।

इमरान और उनकी टीम ने लक्षित समूहों, सदस्यों और विभिन्न समाज के सदस्यों और विभिन्न धर्मों के प्रमुखों के साथ छोटी-छोटी सभाएं, रैलियां और मीटिंग्स कर लोगों को यह समझाया कि ए.आई.एम.आई.एम. वास्तव में क्या कर रही है और उसके गेम प्लान को विफल करने के लिए यह समझना कितना जरूरी है।

इमरान ने तेलंगाना में 26 रैलियां कीं और पूरे क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ मीटिंग्स कर अपनी स्ट्राइक रेट 100 के आसपास रखी। राजस्थान में उन्होंने सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया था। कांग्रेस ने इस सातों में ही जीत दर्ज की थी। ये निर्वाचन क्षेत्र थे- लाडनूं, धौलपुर, उदयपुरवाटी, सीकर, बायतू, किशनपोल और आदर्श नगर।

मध्य प्रदेश में उन्होंने जबलपुर और बुरहानपुर में चुनाव प्रचार किया था, जिसमें एक पर कांग्रेस जीती और दूसरी पर कांटे की टक्कर रही।

उनकी टीम लोकसभा चुनाव के लिए पहले से ही मुस्तैद है और पार्टी नेतृत्व द्वारा दी जाने वाली जिम्मेदारी के आधार पर ही वह अपनी चुनावी रणनीति बनाएंगे।

प्र.मंत्री मोदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"विकसित भारत संकल्प यात्रा" प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। उनका नमो घाट पर मां गंगा की आरती करने का कार्यक्रम है, जहां काशी-तमिल समागम के द्वितीय चरण की शुरुआत पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाएगा।

अन्ततोगत्वा हो ही गया महुआ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लगाया कि एथिक्स कमेटी में मोईत्रा तीन बार आई हर बार उनका व्यवहार बेहद उददण्ड था। सारंगी ने तिवारी के आरोप का जवाब दिया कि मोईत्रा को सदन में अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया।

तृणमूल सांसद सूदीप बंदोपाध्याय और कल्याण बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से कहा कि महुआ को बोलने दिया जाए। स्पीकर ने 2005 का सोमनाथ चटर्जी का हवाला दिया जब दस सांसदों को सवाल पूछने के एवज में कैश लेने का आरोपी ठहराकर निष्कासित किया गया था तब तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया था।

बिड़ला ने कहा कि तत्कालीन स्पीकर चटर्जी ने कहा थाकि संसदीय कमेटी के समक्ष बयान दिया जा चुका है इसलिए सदन में बोलने का हक नहीं है। हम उसी परम्परा का सम्मान कर रहे है।

इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने रिपोर्ट पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिए जाने पर विरोध जताया। उन्होंने इस दिन को काला अध्याय बताया तो प्रहलाद जोशी ने कहा कि महुआ के आचरण ने लोकतंत्र पर दाग लगाया है। सदन तो इसे सुधार रहा है।

तृणमूल सांसदों ने कहा कि एथिक्स पैनल ने उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी के शपथ पत्र व जय अनन्त देहद्राई की शिकायत पर भरोसा किया पर उनका परीक्षण नहीं किया। कल्याण बनजीर ने कहा कि सिर्फ हलफनामे के आधार पर आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते है।

मोईत्रा ने कहा कि मुझे आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है जो है ही नहीं।

इसी बीच भाजपा ने कहा कि मोईत्रा ने खुद माना है कि उन्होंने उद्योगपति को संसद की लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड दिया था।

विपक्षी गठबंधन ने भी लोकसभा के एथिक्स पैनल पर सवाल उठाया और भाजपा सरकार परबदले की राजनीति करने का आरोप लगा था।

भारी शोरगुल के बीच शुक्रवार को सदन में रिपोर्ट रखी गई। विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक नए काले अध्याय की शुरुआत हो रही है।

बसपा नेता दानिश अली, जो एथिक्स पैनल में शामिल थे, ने भी महुआ से पूछे जाने वाले सवालों को लेकर वॉक आुट किया था।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अधूरी है क्योंकि पैनल के सभी सदस्य मौजूद नहीं थे। पांच सदस्यों ने वॉक आउट किया था। क्योंकि पैनल अध्यक्ष घटिया सवाल पूछ रहे थे। यह बात मीटिंग के विचरण में दर्ज है। हम रिपोर्ट पर चर्चा चाहते है।

भाकपा के राज्यसभा सदस्य बिनॉय विश्वम ने इसे बदले की राजनीतिक करार दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरुर ने रिपोर्ट का अधूरा दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह रिपोर्ट वास्तव में किसी भी रिपोर्ट में मूल मकसद पर खरी नहीं उतरती है। इसमें नाटकीय तरीके से निष्कासन की सिफारिश की गई है इसे बिना किसी चर्चा के मात्र ढाई मिनट में स्वीकार कर लिया गया। आरोप लगाने वालों से जिरह नहीं की गई। निष्कासित किए जाने वाले सांसद को अपने पक्ष में कुछ कहने का मौका नहीं दिया गया।"

शिव सेना के उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि जिस हलफनामे पर रिपोर्ट आधारित है उस गवाह को बुलाया तक नहीं गया। जब मोईत्रा को बुलाया गया तो उनका चरित्र हनन किया गया।

कांग्रेस सांसद कार्ती चिदम्बरम ने कहा कि यह भाजपा का दुस्साहस है अगर वे ऐसा ही करते रहे तो महुआ को 50,000 ज्यादा वोट मिलेंगे।

गर्ल्स हॉस्टल में घुसा पैंथर, छह घंटे बाद आया पकड़ में

- **हॉस्टल परिसर में दौड़ता रहा, छात्राएं डर कर कमरे में बंद हो गई।**
- **वन विभाग की टीम ने ट्रेंकुलाईज कर किया रेस्क्यु।**

उदयपुर, 8 दिसम्बर (कासं)। उदयपुर शहर में शुक्रवार सुबह आबादी क्षेत्र में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में पैंथर घुस गया। पैंथर घुसने के बाद वहां भय का माहौल हो गया और हॉस्टल में मौजूद छात्राएं, जो 8-10 की संख्या में थी कमरे में बंद हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने छह घंटे की मशक्कत के बाद उसे ट्रेंकुलाईज कर पकड़ा।

जानकारी के अनुसार शहर के हिरणमगरी सेक्टर 4 क्षेत्र में स्थित परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल में सुबह 10 बजे वहां के कर्मचारियों ने एक पैंथर का मूवमेंट देखा। इस संबंध में हॉस्टल संचालक रजत ने इसकी जानकारी हॉस्टल निदेशक हरीश राजानी को दी तो उन्होंने सीसीटीवी में देखा तो दोपहर 12 बजे पैंथर के घुसने की पुष्टि होने पर वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। करीब 15 से 20 मिनट में वन विभाग व वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच गई और पैंथर को रेस्क्यू करने की कवायद शुरू की।

उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) अजय चित्तौड़ा ने बताया कि "छात्रावास की इमारत काफी बड़ी है सबसे पहले हमने पैंथर कहां है इसकी खोज शुरू की। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से उसका मूवमेंट छात्रावास की तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर देखा गया। पैंथर दूसरी व तीसरी मंजिल पर बार-बार सीढ़ियों से उतर कर सीढ़ी के नीचे बनी बुखारी में जाकर छुप रहा था जिससे उसे रेस्क्यु नहीं कर पा रहे थे। टीम ने रेस्क्यु अभियान जारी रखते हुए बुखारी को बंद किया इसके बाद सहमा हुआ पैंथर शॉट पोइंट पर दिखाई देने लगा और गेट का एंगल काट शॉट लगाया गया जो नहीं लगा। इसके बाद इमारत में मौजूद एक कमरे में जाकर वहां से एक ईंट हटाकर उस पर शॉट लगाया गया जो सटीक लगा और पैंथर बेहोश हो गया।

इस पूरे रेस्क्यु अभियान में करीब 6 घंटे का समय लगा। हॉस्टल में घूमने के दौरान वहां मौजूद एक कर्मचारी राजू जो नीचे की ओर से आ रहा था और पैंथर दूसरी मंजिल की सीढ़ि यों की ओर चढ़ रहा था गनीमत रही कि उसकी नजर पैंथर पर पड़ गई और वह पुनः सीढ़ि यां चढ़ कर ऊपर अपने कमरे में चला गया वहीं छात्रावास की अधिकांश छात्राएं भी कॉलेज गई हुई थी ऐसे में वहां केवल आठ से दस छात्राएं ही मौजूद थी जिन्हें सूचना मिलने के बाद उन्होंने अपने कमरे बंद कर लिए।

शिमला में बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे

- **13.53 किलोमीटर लम्बा रोपवे 1555 करोड़ रू. की लागत से बनाया जा रहा है।**

शिमला, 8 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। शिमला शहर में बड़ रही जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण साबित होने वाला हैं।

प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि ,1555 करोड रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट शहर में 13.55 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 13 स्टेशन होंगे।

उन्होंने बताया कि, शिमला में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह रोपवे प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । अक्टूबर तक सभी ओपचारिकताएं पूरी कर काम शुरू कर लिया जाएगा।

अग्निहोत्री ने कहा कि शिमला में बनने वाला यह प्रोजेक्ट जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी प्रकार की एनओसी और टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

ढ़ ाई साल में प्रोजेक्ट का पहला फेज शुरू कर दिया जाएगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 1555 करोड़ रुपए का य़ह प्रोजेक्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक से फंडेड है । उन्होंने कहा कि यह रोपवे प्रोजेक्ट शिमला शहर में 13.55 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 13 स्टेशन बनेंगे जिसमें रोपवे की तीन लाइने चलेगी। रोपवे के पूरे प्रोजेक्ट में 660 ट्रोलिया चलेगी।

उन्होंने बताया कि, लोगों की सुविधा के लिए रोपवे प्रोजेक्ट में किराया बस किराए के समान ही रखा जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके और हिमाचल देश के लिए भी मॉडल बन सके। आने वाले समय मे परमाणु से विश्व का सबसे बड़ा एक और प्रोजेकट बनाया जाएगा।

यह 38 किलोमीटर का विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेकट होगा। उन्होंने बताया कि चिंतपूर्णी माता का 75 करोड़ रुपए से प्रोजेक्ट बनेगा। इस क्षेत्र मे निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार दवारा नीतियों मे बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल मे अब रोप वे ही एक रास्ता है जिसके माध्यम से यातायात को सुचारु और आसान बनाया जा सकता है। अग्निहोत्री ने बताया कि शिमला में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह रोपवे प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ढ़ ाई साल में प्रोजेक्ट का पहला फेज शुरू कर दिया जाएगा, जबकि प्रोजेक्ट को पूरा होने में पांच साल का वक्त लगेगा। वैसे तो भारत के उत्तराखंड, गुजरात व मुंबई से भी सबसे लंबे रोप वे के दावे आते रहे हैं, लेकिन दूरी के हिसाब से तारा देवी से संजौली ही सबसे लंबा रोप वे होगा।

बारामूला स्टेडियम बना जनरल रावत स्टेडियम

श्रीनगर, 8 दिसंबर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को बारामूला में झेलम स्टेडियम जांबाजपोरा का नाम बदलकर दिवंगत पूर्व सी.डी.एस. जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की मंजूरी प्रदान की है।

एक सरकारी आदेश के अनुसार, बारामूला के जांबाजपोरा स्थित झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम करने की मंजूरी प्रदान की जाती है। देश के पहले सी.डी.एस. जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों को लेकर जा रही हेलीकॉप्टर आठ दिसंबर, 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिससे उनकी मौत हो गई। कश्मीर में जनरल रावत का पिछला कार्यकाल बारामूला स्थित 19 इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का था। इस कार्यकाल के दौरान ही जनरल रावत बारामूला शहर में कई लोगों के चहेते बन गए थे।

ई.वी.एम. की भूमिका फिर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को लेकर बहस छेड़ दी है और वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को निष्पक्ष रखने के लिए वह ई.वी.एम. के दुरूपयोग के मुद्दे पर "इंडिया" गठबंधन की मीटिंग में चर्चा करेगी।

मध्य प्रदेश के ए.आई.सी.सी. प्रभारी महासचिव सी.पी. मित्तल ने कहा कि चुनावों के दौरान जब जनता का मूड भाजपा के खिलाफ था, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस-भाजपा के बीच हार जीत और प्राप्त मतों का भारी अन्तर एक पहेली बना हुआ है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर आश्चर्य जताया कि कांग्रेस प्रत्याशी अपने मजबूत माने जाने वाले बूथों पर भी सिर्फ 50-60 वोट ही प्राप्त कर सके।

सी.डब्ल्यू.सी. मैम्बर कमलेश्वर पटेल ने बताया कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैण्ड और आयरलैण्ड के चुनावों में ई.वी.एम. का प्रयोग नहीं किया जाता।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस जैसी विचारधारा पर चलने वाली अन्य पार्टियों के साथ ई.वी.एम. के मुद्दे पर चर्चा करते रहे हैं, कहते हैं कि "चिप लगी किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। क्या हम प्रोफैशनल हैकर्स को हमारे लोकतंत्र को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं। माननीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट क्या आप कृपया हमारे लोकतंत्र को बचाएंगे?"

वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा ने ई.वी.एम. को दोष दिया था और वर्ष 2004 में एन.डी.ए. की हार के बाद भाजपा नेता एल.के. अडवानी ने ई.वी.एम. की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908